भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 28

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

स्कूली शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

†28. श्री जी. सेल्वमः

श्री धनुष एम. कुमारः

श्रीमती मंजुलता मंडल:

डॉ. पोन गौतम सिगामणि :

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्कूली शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तरह के सम्मेलन के आयोजन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें किन – किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार की राज्य स्तर पर विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना है, जिसे स्कूलों में अधिगम स्तर के विश्लेषण और निदान के उद्देश्य हेतु जिला/ब्लॉक/स्कूल स्तर के साथ एकीकृत करके एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अधिगम परिणामों में और सुधार किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत, जीवंत और 21वीं सदी की आवश्यकताओं और एक नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.): जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, गुजरात के सहयोग से महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में 01 और 02 जून, 2022 को दो-दिवसीय स्कूल शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन में चर्चा किए गए मुख्य बिंदु/मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1) एनईपी 2020 कार्यान्वयन के रोल आउट और प्रगति पर चर्चा।

2) स्कूल पुनः खुलने के बाद अधिगम हानि को पूरा करने के लिए विचारों और कार्यनीतियों का आदान-प्रदान करना

3) अधिगम परिणामों (एलओ) की निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग

गांधीनगर, गुजरात में 01 और 02 जून, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा मंत्री सम्मेलन में 153 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया था।

छात्रों के नामांकन की निगरानी करने, उनके अधिगम स्तर में प्रगति, स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्यधारा में लाने, पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षकों और स्कूलों द्वारा अपेक्षित सहायता आदि पर नज़र रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने की दिशा में, समग्र शिक्षा के तहत विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 स्कूली शिक्षा में व्यापक परिवर्तन पर - "भारतीय लोकाचार में निहित ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत का रूपांतरण करने में प्रत्यक्ष योगदान देती है, अर्थात भारत को स्थायी रूप से समान और जीवंत ज्ञान समाज के रूप में, जिसमें सभी को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके परिवर्तन की परिकल्पना करती है ताकि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके।

इस कार्य में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों का समग्र उन्नति (सार्थक) नामक एक संकेतात्मक और सुझावात्मक कार्यान्वयन योजना जारी की है। विभाग ने एनईपी 2020 की सिफ़ारिशों से अपनी मौजूदा योजनाओं अर्थात समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को भी संरेखित किया है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण पहल जैसे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ़एलएन) के लिए निपुण भारत मिशन, विश्लेषणात्मक अधिगम के लिए संरचित मूल्यांकन (सफल), परख (निष्पादन मूल्यांकन, समीक्षा, और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण), विद्या प्रवेश, विद्यांजलि 2.0, आदि शुरू किए गए हैं।

*****